दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

रीडर, डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

दृष्टिकोण प्रकाशन

WZ-724, पालम गांव, नई दिल्ली-110045

वर्ष : 11 अंक : 5 ❑ सितम्बर–अक्टूबर, 2019

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबोरोग, ओन्टारियो

डॉ. दया शंकर तिवारी
राजधानी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर

डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची

डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना

डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा

डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

डॉ. अमर कान्त सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, भागलपुर

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट–5, मयूर विहार, फेज–I, दिल्ली–110091
फोन : 011–22753916
e-mail : editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com

©Editorial India

Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

मूल्य: ₹ 1500.00

मुद्रक एवं प्रकाशक निर्मल कुमार सिंह द्वारा WZ-724, पालम गांव, नई दिल्ली–110045 से प्रकाशित तथा ट्राइडेंट इन्टरप्राइजेज, डी–204, सेक्टर–10, नोएडा, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश से मुद्रित

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

भारत-अमेरिका संबंधों में खटास

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च, 2019 को अमेरिकी कांग्रेस को पत्र लिखकर भारत को व्यापार में दी जानेवाली सुविधा जीएसपी यानि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफेरेंसेस को वापस लेने की इच्छा जतायी थी, उनका कहना है कि अमेरिका को अपने बाजारों उपयुक्त पहुंच का आश्वासन देने में भारत असफल रहा है। ट्रंप ने तुर्की से भी इस सुविधा को वापस लेने का फैसला लिया है। अब अमेरिकी सरकार ने भारत से भी जीएसपी के अंतर्गत वरीयता के आधार पर आयाता की सुविधा वापस ले ली है। अमेरिका कई देशों की जीएसपी की सुविधा देता है। इसके अंतर्गत अमेरिका में कई भारतीय सामानों को शुल्क के बिना आयात की अनुमति है। यह सुविधा वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं, इंजीनीयरिंग वस्तुओं तथा कीमती पत्थरों एवं आभूषणों आदि पर उपलब्ध है। वर्ष 2018 में अमेरिका को होनेवाले भारतीय निर्यात का कुल मूल्य 54.5 अरब डॉलर था, जिसमें से मात्र 5.6 अरब डॉलर के निर्यात में ही जीएसपी सुविधा है और इससे भारत को मात्र 0.19 अरब डॉलर के आयात शुल्क की बचत होती है।

भारत से आयात कम करने के लिए अमेरिका अन्य तरीके से भी पूरा प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ समय से वह हमारे सामान पर आयात शुल्क बढ़ा रहा है, जिससे हमारे निर्यात प्रभावित हो रहे हैं, वहीं भारत का इस बारे में रुख ज्यादा नरम रहा है, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के सामान पर आयात शुल्क बढ़ाता है तो जबाब में वह देश भी आयात शुल्क बढ़ाता है। लेकिन, अमेरिका के प्रति भारत की अपेक्षित जवाबी कार्यवाही स्थगित की जा रही है। ऐसी नरमी दूसरे देश को आक्रामक होने का मौका देती है।

संकेत है कि अमेरिकी वस्तुओं पर जो आयाता शुल्क 16 मई से बढ़ाये जाने थे, उन्हें एक महीने के लिए टाल दिया गया है। शायद सरकार को उम्मीद है कि अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। फिलहाल, अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में मात्र 21.3 अरब डॉलर का ही घाटा है, जबकि चीन के साथ उसका घाटा 566 अरब डॉलर है। इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन का भारत के प्रति ऐसा व्यवहार दोस्ती पर प्रश्न-चिन्ह लगाता है। अफगानिस्तान में ढ़ांचागत विकास के भारतीय प्रयासों का मजाक उड़ाना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ आवश्यक सख्ती न दिखाना, अमेरिका पर संदेह को पुख्ता करता है। अमेरिका को लग रहा है कि ट्रंप की अफगानिस्तान से निकलने की नीति में पाकिस्तान सहयोगी हो सकता है।

अमेरिका अपनी कंपनियों के हित के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और वह सरकारों पर दबाव बनाता है। भारत में कई ऐसी अमेरिकी कंपनियां है, जिनके कार्यकलाप भारतीय हितों के अनुरूप नहीं है। कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि वह अपना पेटेंट कानून बदल कर अमेरिकी कंपनियों को दवाइयों पर पेटेंट अवधि खत्म होने के बाद भी फिर से पेटेंट की अनुमति दे दे। पेटेंट कानूनों में बदलावों के लिए भी दबाव बनाया गया। भारत सरकार ने जब अमेरिकी ई-कार्मस कंपनी एमेजॉन पर शिकंजा कसा, तो अमेरिका ने फिर से इस नीति को बदलने की मांग की। यह आश्चर्यजनक भी है क्योंकि ट्रंप अपने देश में स्वयं एमेजॉन के घोर विरोधी हैं।

आज अमेरिका को व्यापार में भारत से 25 गुणा ज्यादा घाटा चीन से है, उसके बावजूद वह चीन से समझौते का हाथ बढ़ा रहा है और भारत के प्रति सख्ती कर रहा है। उसने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया था। अमेरिका की इस मांग को मानने पर उसे तो कोई फायदा होगा नहीं, अलबत्ता चीन के मोबाइल फोन पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में भारत आने लगेंगे। भारतीय नेतृत्व को अमेरिका के साथ सख्ती से पेश आना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का यह रुख उसके आर्थिक हितों से ज्यादा उसकी दादागिरी को दर्शाता है।

अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए कि भारत उसके आर्थिक और सामरिक हितों के लिए उपयोगी देश है। आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। अमेरिका द्वारा भारत को निर्यात होनेवाली एक बड़ी मदद पेट्रोलियम तेल और गैस है, जो 4.5 अरब

डॉलर के बराबर है। इसके और बढ़ने की संभावना है। अमेरिका द्वारा भारत को अगले सात सालों में 300 बोइंग विमान बेचे जाने हैं, जिनकी कुल लागत 39 अरब डॉलर है। इसके अतिरिक्त अमेरिका से अनेक रक्षा सौदे भी हो रहे हैं। इसलिए अमेरिका के साथ भारतीय व्यापार का अधिशेष घाटे में बदल सकता है।

अमेरिका को समझना होगा कि भारत के साथ सहयोग से वह अपने हितों को बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकता है। भारत सरकार के लिए देश में रोजगार, जन स्वास्थ्य और अपने उद्योगों की रक्षा प्राथमिक कर्त्तव्य है। इसलिए चाहे एमेजॉन और वालमार्ट पर शिकंजा कसने की बात हो या भारत के इलेक्ट्रानिक और टेलीकॉम उद्योग के संरक्षण हेतु आयात शुल्क बढ़ाने की बात हो, भारत की चिंताओं को समझते हुए अमेरिका को अपना रुख ठीक करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो भारत को अपने हितों की रक्षा करनी ही होगी।

संपादक